

MR. SPEAKER: I propose that we should continue sitting at night also, so that you may know the value of time.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Regarding other matters mentioned by the hon. Members, in so far as they relate to the Central Government, they will be duly conveyed.

अध्यक्ष महोदय : आप रात को बैठेंगे तो मुबह ड्राइजी फील करेंगे। आपको रात में जल्द बैठना चाहिए। श्री मधु लिमये।

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं बार-बार अकाल और बाढ़ के बारे में कहता रहा हूँ, इस बार मैंने लिखकर नहीं दिया है। आप हमेशा कहते हैं मान लिया गया है लेकिन समय नहीं मिलता है। कई दफा आपने आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कमी तसल्ली भी होती है या नहीं? सारे दिन लगे रहते हैं और अभी बाढ़ रह गई।

13.10 hrs.

STATEMENT BY MEMBER RE.
STEPS TO REDUCE THE PRICES
OF COTTON FABRICS AND PRO-
FITS OF TEXTILE MILLS

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, 27 जुलाई, 1973 को मैंने व्यापार मंत्री से एक प्रश्न द्वारा यह जानना चाहा कि क्या सरकार को इस बात की इत्तिला है कि 1972-73 में सूती मिलों ने अनापशनाप मुनाफा कमाया है। मैंने यह भी पूछा था कि सरकार मिल कपड़े के दामों को घटाने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रही है। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के तौसरे हिस्से का यह जवाब दिया था कि सरकार को मिलों के मुनाफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह उत्तर न केवल गलत था बल्कि मिल वालों

की मुनाफाखोरी पर और सरकार की पूंजी-परस्त नीति पर चादर बिछाने का यह एक जानबूझ कर किया हुआ प्रयास था। मंत्री महोदय का जो स्पष्टीकरण आपने मुझे दिया है उसमें कहा गया है :

“यह निस्संदेह है कि संसद सदस्य श्री मधु लिमये ने अने 25 जून, 1973 के पत्र में मिलों के मुनाफे के बारे में व्यापार मंत्री के पास कुछ आंकड़े भेजे थे। लेकिन श्री मधु लिमये के आंकड़ों की सत्यता और उसके आधार के बारे में मंत्रालय को कोई इत्तिला नहीं मिल सकी। सरकार के पास इसके बारे में कोई तिलतिलेवार जानकारी नहीं थी। इन स्थिति में हम श्री मधु लिमये के आंकड़ों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। जब सरकार को दूसरी जानकारी नहीं रहती तो साधारणतः सरकार आधिकारिक सूत्रों पर निर्भर रहती है।”

यह खुलासा बहुत हास्यास्पद है। क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि दाम, मुनाफे आदि के बारे में वित्तीय पत्रिकाओं में जो खबरें आती हैं उनको वह पढ़े और उसकी गहराई में जा कर उसका अध्ययन करे? “कामरी” यह एक ख्यातिप्राप्त वित्तीय साप्ताहिक है। इसमें कम्पनियों के बारे में हर सप्ताह समाचार छलते हैं। अप्रैल 1973 से लेकर 27 जुलाई तक यानी मेरे प्रश्न के उत्तर के दिन तक इस पत्रिका ने दर्जनों मिलों के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की है। इस पत्रिका में कम्पनियों के बारे में जो समाचार छपे हैं उनकी सत्यता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करते हैं। इन समाचारों को पढ़ने से इसके बारे में कोई सन्देह नहीं रहता कि

1972-73 में मिल मालिकों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। सरकार और मिल मालिकों के बीच में जो गठबन्धन था, उसके चलते काश्तकार, छोटा बुनकर और साधारण उपभोक्ता इन तीनों के हितों की होली की गई है। मैं अभी सूचुरी, विक्टोरिया तथा नूतन के रिपोर्ट्स तथा कुछ मिलों के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ :

| | |
|----------------|--------------------------|
| पोटार मिल्स | 52 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| गायकवाड़ | 92 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| लक्ष्मी विष्णु | 100 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| विक्टोरिया | 209 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| नवसारी | 245 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| एल्लिन | 254 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| बोरिया | 750 प्रतिशत अधिक मुनाफा |
| विक्रम | 1500 प्रतिशत अधिक मुनाफा |

वित्त मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा था कि मैं व्यापार मंत्री से पूछ रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। ये आंकड़े वह भी देखें।

इस मामले में मेरे पास जो जानकारी थी वह स्वयं मैंने मंत्री जी को भेजी थी। मिल के मुनाफों के आंकड़ों के बारे में न वित्तीय पत्रिकाएँ और न मेरे जैसे सदस्य कोई फर्जी आंकड़ों को तैयार करते हैं। ये आंकड़े वित्तीय पत्रिकाएँ मिलों और कम्पनियों के जो वार्षिक रिपोर्ट्स होती हैं उन्हीं से एकत्रित करती हैं। ये वार्षिक रिपोर्टें कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दायर की जाती हैं। अगर व्यापार मंत्री मेरे आंकड़ों की सत्यता को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें व्यापार मंत्रालय के तहत काम करने वाले टैक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय से जानकारी हासिल करनी चाहिये थी। टैक्सटाइल कमिश्नर के दफ्तर का यह फर्ज है कि सूती उद्योग में जो परिवर्तन होते

रहते हैं उनकी सही जानकारी रखें। लेकिन टैक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय मिल मालिकों से मिला हुआ था और सत्य को छिपाने का काम कर रहा था। अगर मंत्री महोदय चाहते तो कम्पनियों के रजिस्ट्रार से भी तथ्यों को प्राप्त कर सकते थे, मगर यह भी उन्होंने नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, किस संदर्भ में इस सवाल को उठाया गया था, यह विचारणीय है (इंटरप्राइज) अध्यक्ष महोदय, आपने जो पास किया है, जिसको आपने मंजूर किया है, उसी को पढ़ कर मैं सुना रहा हूँ। एक शब्द भी नहीं जोड़ रहा हूँ। सूत और सूती कपड़े के दामों में जो भयंकर वृद्धि हुई थी, उसको लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी। यह भी बताया गया था कि जनवरी 1971 और अप्रैल 1973 के बीच में विभिन्न जाति की रई की कीमतें 28 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक घट गई थीं। रई के दामों के बारे में मंत्री महोदय आंकड़े के खेल खेल रहे थे। उन्होंने मिलों के मुनाफों के बारे में जो नकारात्मक उत्तर दिया वह न केवल गलत बयानी थी बल्कि वे अपनी पूंजीपरस्त नीति के भंडाफोड़ से अपने को बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मिल मालिकों की मुनाफाखोरी की जानकारी सारे देश में फैले।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप व्यापार मंत्री को फटकारें उन्हें रेब्रिमांड करें। मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि आप सभी मंत्रियों को चेतावनी दें कि वे गलत बयानी न करें और टालमटोल की नीति न अपनाएं। प्रश्न पूछे जाते हैं सार्वजनिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसलिए मंत्रियों का यह काम है कि तारांकित और अतारांकित सभी प्रश्नों का वे सम्पूर्ण और सही जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय: रेप्रीमांड का हिन्दी अनुवाद बड़ा मुश्किल है मेरे से.....

श्री मधु लिमये : फटकारना और क्या ? यह बिल्कुल करना चाहिये । प्रेसोडेंट चाहते हैं तो मैं पिछले 23 साल के निकाल कर दे सकता हूँ

अध्यक्ष महोदय : रेप्रोमांड का जो किया है वह मेरे खयाल में ठीक नहीं, उचित नहीं है ।

श्री मधु लिमये : सही अनुवाद है । एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : डिक्ज ; री देखनी पड़ेगी ।

श्री मधु लिमये : मुश्किल यही है कि आर्यक सुविधा के लिए मैंने लिखकर अंग्रेजी में दिया ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): Mr. Speaker, Sir, Shri Madhur Limaya's Question (Unstarred No. 900) related to prices of cotton and cloth and to profits made by textile mills. Information that was available with Government was furnished in reply and there has been no attempt to mislead the House.

Reference was made in the question to "fantastic profits made by the textile mills ranging between 50 to 1500 per cent". From the letters of the Honourable Member dated 12th June 1973 and 25th June 1973 it was clear that this was being stated on the basis of figures cited by him for 11 mills. Reference has now been made by the Honourable Member in the statements, to the effect that figures have been given in certain financial journals to this effect. It will be appreciated that whatever figures might have been given in these journals, these would have to be duly processed and checked by Government before any statement could be made on the floor of the House. Moreover, figures given in respect of 11 mills could not be taken as representative of the industry as a whole. In this context the answer given cannot be said to be either incorrect or misleading.

We have always tried to furnish true and correct information in regard to all aspects of the textile industry, including questions of prices, of cotton cloth etc. The contentions of the Honourable Member are under these circumstances untenable and unfair.

श्री मधु लिमये : उनका जवाब था :

"Government has received no information"

क्या यह सही जवाब था ? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं ।

MR. SPEAKER: There can be no debate on it now.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): He is not ready to be reprimanded.

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं करना चाहता । चुन लेता हूँ

श्री मधु लिमये : 115 का मतलब यही है कि गलती को पकड़ा जाए । आपको उसके बारे में फौसला लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा ।

श्री मधु लिमये : आप तो जब हमारी गलती नहीं भी होती है तब भी पकड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो हिन्दी तर्जुमा किया है, उसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूँ ।

13.18 hrs

RE. INCIDENTS AT SHRADDHANAND COLLEGE, DELHI

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (स्वाध्याय) : हमने 377 में आपसे इजाजत मांगी थी कि दिल्ली के कालेज का मामला उठाने दिया जाय । बिना प्रिंसिपल की इजाजत के पुलिस श्रद्धानन्द कालेज में चली गई; कालेज के भीतर टीचर गैस चलाई गई, दो घंटे तक